

कार्यकारी सारांश

राजस्थान सेकेंडरी टाउन डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट, (RSTDSP), निवेश परियोजनाओं का चौथा चरण एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा वित्तपोषित है और राजस्थान अर्बन ट्रिकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RUDSICO) द्वारा कार्यान्वित है, जिसे पहले राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट परियोजना (आरयूआईडीपी) के नाम से जाना जाता था। आरएसटीडीएसपी लगभग 14 शहरों में पानी और अपशिष्ट जल सेवाओं में सुधार की दिशा में राजस्थान सरकार के चल रहे प्रयासों का समर्थन करेगा। RSTDSP सेक्टर, ऋण के माध्यम से 20,000-115,000 के बीच आबादी वाले माध्यमिक शहरों में जल आपूर्ति और सीवरेज (WSS) सेवाओं में सुधार करना चाहता है। परियोजना निम्नलिखित प्रभावों के साथ संरेखित है: (i) राजस्थान के सभी शहरी क्षेत्रों में पीने योग्य, सस्ती, विश्वसनीय, न्यायसंगत और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ पेयजल आपूर्ति तक पहुंच में सुधार होगा। (ii) शहरी आबादी, विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। राजस्थान के माध्यमिक शहरों में शहरी सेवा वितरण में सुधार होगा।

2. रतनगढ़ सीवरेज उपपरियोजना आरएसटीडीएसपी के निवेश घटक के तहत प्रस्तावित उप परियोजनाओं में से एक है। फिलहाल शहर में सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। सीवरेज सिस्टम की कमी के कारण, अधिकांश घर सीवरेज के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक पर निर्भर हैं। सेप्टिक टैंकों और गंदे पानी को खुले नालों में छोड़ दिया जाता है जो अंततः निचले इलाकों और शहर के बाहरी इलाके में प्राकृतिक नालियों में जमा हो जाता है।

3. संभावित प्रभावों की जांच और आकलन- एडीबी को, बैंक के संचालन के सभी पहलुओं में पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है, और पर्यावरण मूल्यांकन की आवश्यकताओं को एडीबी के सुरक्षा नीति वक्तव्य (एसपीएस), 2009 में वर्णित किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अनुसार, इस उप-परियोजना को ईआईए अध्ययन या पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। सीवरेज के लिए, उप-परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन, एडीबी रैपिड एनवायरनमेंटल असेसमेंट (आरईए) चेकलिस्ट का उपयोग करके किया गया है। पूर्व-निर्माण, निर्माण और संचालन चरणों के संबंध में संभावित नकारात्मक प्रभावों की पहचान की गई थी। यह प्रारंभिक पर्यावरण परीक्षा (आईईई) रतनगढ़ टाउन सीवरेज उप-परियोजना के तहत प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के घटकों को संबोधित करती है।

4. वर्गीकरण (i) प्रारंभिक विस्तृत डिजाइन, और (ii) पर्यावरण के प्रति संवेदनशील घटकों की सबसे अधिक संभावना के आधार पर रतनगढ़ टाउन सीवरेज उप-परियोजना के लिए पर्यावरण मूल्यांकन किया गया है। पर्यावरण मूल्यांकन में सीवरेज कार्यों के लिए एडीबी की आरईए चेकलिस्ट (REA Checklist) और "अशमन परिदृश्य चेकलिस्ट (No Mitigation Scenario Checklist)" का उपयोग किया गया था। रतनगढ़ टाउन सीवरेज उप-परियोजना के पर्यावरणीय मूल्यांकन से कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव होने की संभावना नहीं है जो अपरिवर्तनीय, विविध या अभूतपूर्व हैं। संभावित प्रभाव, ज्यादातर साइट-विशिष्ट होते हैं और उनमें से कुछ अपरिवर्तनीय होते हैं। ज्यादातर मामलों में शमन उपायों को निर्माण स्थलों पर आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले सरल उपायों के साथ डिजाइन किया जा सकता है और जो कि सिविल कार्य ठेकेदारों को पता हो।

5. रतनगढ़ टाउन सीवरेज उप-परियोजना को एसपीएस के अनुसार पर्यावरण श्रेणी बी के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि कोई महत्वपूर्ण प्रभाव परिकल्पित नहीं है। तदनुसार, यह आईईई पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करती है और यह सुनिश्चित करने के लिए शमन और निगरानी उपाय (Mitigation and Monitoring Measures) प्रदान करता है कि परियोजना के परिणामस्वरूप कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

6. इस उप-परियोजना की प्रारूप आईईई (Draft IEE), संभाव्यता (Feasibility) /प्रारंभिक डिजाइन के आधार पर एडीबी द्वारा तैयार और अनुमोदित की गई थी और इस डीबीओ पैकेज की बोली और अनुबंध में शामिल की गई थी। स्कोप, स्थान आदि में किसी भी परिवर्तन सहित अंतिम उप-परियोजना डिजाइनों को दर्शाने वाली अद्यतन (updated) आईईई, और निर्माण शुरू होने से पहले एडीबी द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है। चूंकि डिजाइनों

को जोन/सबजोन/घटक-वार अंतिम रूप दिया जा रहा है, इसलिए आईईई को चरणों में अपडेट करने की भी योजना है ताकि उन घटकों के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके जिनके लिए डिजाइन तैयार किए गए हैं। यह इस पैकेज का दूसरा अद्यतन (updated) आईईई है। पहले अद्यतन IEE को अगस्त 2021 में ADB द्वारा अनुमोदित किया गया था और ADB और RUIDP वेबसाइटों में इसका खुलासा किया गया था। सीवर नेटवर्क और अन्य परियोजना घटकों की स्वीकृति स्थिति में परिवर्तन के कारण इसे अद्यतन (दूसरा अद्यतन) किया जा रहा है। पहले अद्यतन आईईई में; कुल प्रस्तावित 145 किमी सीवर नेटवर्क (लगभग 77.9%) में से 113 किमी को मंजूरी दी गई थी। टीईईआर और टीईएसआर की क्षमता में भी बदलाव किया गया और 2 सीआरएमसी के स्थानों को अंतिम रूप दिया गया। वर्तमान में, आईईई के दूसरे अद्यतन के दौरान; 144.33 किमी (100%) के साथ सभी 5 क्षेत्रों में पूर्ण सीवर नेटवर्क और 3.5 किमी (100%) की कुल लंबाई वाले दोनों सीवेज पंपिंग मेन को मंजूरी दी गई है। सिविल संरचनाओं के तहत, 6.1 एमएलडी और 3.8 एमएलडी क्षमता के 2 एसटीपी के डिजाइन (पीटीयू, एसबीआर, सीसीटी और टीईएसआर, टीईईआर), 3.8 एमएलडी और 4.6 एमएलडी क्षमता वाले 2 एसपीएस (इनलेट चैंबर, स्क्रीन चैनल और सम्प वेल), 300 केएल और 190 केएल की क्षमता के 2 टीईएसआर, 610 केएल और 380 केएल की क्षमता के 2 टीईईआर और सीआरएमसी भवनों की स्वीकृति के साथ यह पुष्टि की जाती है कि कोई भी नया क्षेत्र परियोजना के डिजाइन में शामिल नहीं है और किसी भी परियोजना घटक के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एडीबी से अनुमोदन के बाद दूसरा अद्यतन आईईई, आईईई के पुराने संस्करण का स्थान लेगा और ठेकेदार पर संविदात्मक रूप से बाध्यकारी होगा।

7. प्रस्तावित कार्य- इसे रतनगढ़ टाउन में एक व्यापक सीवेज सिस्टम विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि घरेलू अपशिष्ट जल को सुरक्षित रूप से एकत्र, उपचार और निपटान / पुनः उपयोग किया जा सके। यह उन क्षेत्रों में, जो वर्तमान में पूरी तरह से विकसित नहीं हैं और सीवर नेटवर्क प्रदान करने के लिए व्यवहार्य नहीं हैं, वहां उपचार सुविधा और मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (एफएसएसएम) प्रणाली सहित भूमिगत सीवेज प्रणाली के संयोजन में प्रदान किया जा रहा है। कुल आधार वर्ष (2021) की आबादी का लगभग 82 प्रतिशत सीवेज सिस्टम द्वारा कवर किया जाना प्रस्तावित है, जबकि शेष 18 प्रतिशत एफएसएसएम द्वारा कवर किया जाएगा। प्रस्तावित उप-परियोजना घटकों में शामिल हैं: (i) 144.33 किमी सीवर नेटवर्क (200-700 मिमी व्यास), जिसमें मैनहोल और 13.66 किमी ट्रेंचलेस शामिल हैं, (ii) हाउस सीवर कनेक्शन -13,100, (iii) 3.80 एमएलडी और 4.60 एमएलडी क्षमता के दो सीवेज पंपिंग स्टेशन (एसपीएस) (iv) 3.5 किमी कुल लंबाई (डीआई K9 सामग्री के 400 मिमी और 450 मिमी व्यास) के साथ 2 सीवेज पंपिंग मेन का निर्माण (v) 3.80 एमएलडी और 6.10 एमएलडी क्षमता के दो अनुक्रमिक बैच रिएक्टर (एसबीआर) प्रक्रिया पर आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) (vi) 300 केएल और 190 केएल क्षमता के दो उपचारित बहिःस्राव भंडारण जलाशय (टीईएसआर), (vii) 610 केएल और 380 केएल क्षमता के 22 उपचारित उत्प्रवाही जलाशय (टीईईआर) 22 के साथ। एम स्टेजिंग, (viii) एसटीपी से डिस्चार्ज प्वाइंट तक आउटफॉल सीवर, अतिरिक्त/अप्रयुक्त उपचारित बहिःस्राव के निर्वहन के लिए, (ix) सीआरएमसी के दो भवनों का निर्माण - नगर पालिका कार्यालय परिसर में सीआरएमसी-1 और सीआरएमसी-2 का निर्माण प्रस्तावित एसपीएस साइट के पास मुख्य गिनानी में कड़वारिया बस स्थान (x) सक्शन और डिस्चार्ज के साथ मोबाइल टैंकर (3500 लीटर क्षमता) द्वारा एफएसएसएम कवर क्षेत्र में सेप्टिक टैंक से सेप्टेज एकत्र करने और लाने की व्यवस्था।

8. पर्यावरण का विवरण- उप-परियोजना घटक रतनगढ़ टाउन और उसके आसपास के इलाकों में स्थित हैं जो कई वर्षों पहले शहरी उपयोग में परिवर्तित हो गए थे, और प्रस्तावित स्थलों पर कोई प्राकृतिक आवास नहीं बचा है। परियोजना स्थानों में या उसके आस-पास कोई संरक्षित क्षेत्र, आर्द्रभूमि, मेंग्रोव या मुहाना नहीं हैं। निकटतम संरक्षित क्षेत्र ताल छपर अभयारण्य है, जो रतनगढ़ शहर से लगभग 55 किमी (हवाई दूरी) दक्षिण-पश्चिम में है। रतनगढ़ जिले की जलवायु अर्ध-शुष्क प्रकार की है। मरुस्थलीय क्षेत्र के कारण, प्राकृतिक जल निकासी

प्रणाली अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है, और क्षेत्र में कोई चैनल / धाराएं नहीं हैं। भारत के भूकंपीय जोनिंग मानचित्र के अनुसार, रतनगढ़ जोन- II के अंतर्गत आता है, जो भारत में कम भूकंप जोखिम वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र को "कम क्षति जोखिम क्षेत्र" कहा जाता है। इस परियोजना के लिए निजी भूमि का कोई अनैच्छिक भूमि अधिग्रहण प्रत्याशित नहीं है। परियोजना स्थल मौजूदा सड़क मार्ग (आरओडब्ल्यू) और सरकारी स्वामित्व वाली भूमि में स्थित हैं। नगर निगम की खाली भूमि पर प्रस्तावित 2 एसटीपी का निर्माण किया जाएगा। साइटें विरल वृक्षों के आवरण और झाड़ियों से आच्छादित हैं, और इन स्थलों पर कोई उल्लेखनीय वन्यजीव नहीं हैं और स्थल निवास से दूर हैं। पंपिंग स्टेशन में गुरुत्वाकर्षण द्वारा सीवेज प्राप्त करने के लिए एसपीएस साइटों को शहर के भीतर, जलग्रहण क्षेत्र के सबसे कम ऊंचाई बिंदु पर प्रस्तावित किया जाता है। एक साइट मौजूदा ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन के बगल में स्थित है, जहां से संचित अनुपचारित सीवेज को पंप किया जाता है। ये निचले इलाके अपशिष्ट जल और ठोस कचरे से भरे हुए हैं, और बहुत ही अस्वच्छ स्थिति पेश करते हैं।

12. संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और शमन उपाय- इस मसौदे में आईईईई, बेहतर बुनियादी ढांचे के स्थान, डिजाइन, निर्माण और संचालन के संबंध में नकारात्मक प्रभावों की पहचान की गई थी। परियोजना के डिजाइन या स्थान के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं थे क्योंकि साइट योजना और प्रारंभिक डिजाइन में विभिन्न उपाय पहले से ही शामिल हैं। रतनगढ़ टाउन के भीतर कोई पर्यावरण या पुरातात्विक रूप से संवेदनशील क्षेत्र नहीं हैं। चयनित एसपीएस, एसटीपी साइटों और सीआरएमसी भवन स्थलों में कुछ पेड़ों (लगभग 10-15 संख्या) को काटने की आवश्यकता हो सकती है। जहां तक संभव हो विस्तृत डिजाइन के दौरान सुविधाओं के लेआउट प्लान में पेड़ों को एकीकृत किया जाएगा। यदि किसी वृक्ष को काटने की आवश्यकता होती है तो प्रतिवृक्ष वृक्षारोपण 1:3 के अनुपात में किया जायेगा। दो प्रस्तावित एसटीपी स्थल बस्तियों से दूर खाली भूमि (235 से > 500 मीटर की दूरी) और कृषि और बंजर भूमि से घिरी हुई हैं। दोनों एसपीएस साइट आवासीय/व्यावसायिक क्षेत्र के करीब हैं इसलिए ट्री बफर जोन, गंध संवेदनशील डिजाइन और स्टैंडबाय पावर व्यवस्था जैसे शमन उपायों का सुझाव दिया जाता है। एसटीपी में, प्रस्तावित एसबीआर तकनीक उन्नत है, एक कॉम्पैक्ट एरोबिक प्रक्रिया में सीवेज का इलाज करती है, इसलिए खराब गंध के कारण समस्या न्यूनतम है। 2015 में सीपीसीबी द्वारा सुझाए गए कठोर निर्वहन मानकों के लिए एसटीपी को डिजाइन करने का प्रस्ताव है। राजस्थान सीवरेज और अपशिष्ट जल नीति, 2016 के बाद, एसटीपी से उपचारित अपशिष्ट को विभिन्न व्यवहार्य उद्देश्यों में पुनः उपयोग किया जाएगा, और विस्तृत डिजाइन के दौरान एक पुनः उपयोग योजना तैयार की जाएगी। अपशिष्ट जल और कीचड़ के सुरक्षित पुनः उपयोग के लिए विभिन्न उपाय सुझाए गए हैं। उपचारित बहिःस्राव की अधिकता/अधिशेष भूमि पर निस्तारित किया जाएगा। गुआशाला में एसटीपी 2 में उपचारित अपशिष्ट का पूरी तरह से गौशाला (मवेशी देखभाल केंद्र) परिसर के भीतर सिंचाई के लिए उपयोग किया जाएगा।

10. निर्माण के दौरान संभावित प्रभावों को महत्वपूर्ण लेकिन अस्थायी माना जाता है और शहरी क्षेत्रों में निर्माण के सामान्य प्रभाव हैं, और इसे कम करने के लिए अच्छी तरह से विकसित तरीके हैं। पंपिंग स्टेशनों के लिए तकनीकी रूप से उपयुक्त निचली भूमि में दो एसपीएस साइटों का चयन किया जाता है। इन दोनों स्थानों पर वर्तमान में साइट अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट से भरी हुई है, जिसकी निकासी एसपीएस के निर्माण के लिए आवश्यक है। हानिकारक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और कचरे को सुरक्षित रूप से संभालने और निपटाने की आवश्यकता को देखते हुए, उचित शमन उपायों का सुझाव दिया जाता है।

11. सीवर लाइन डालने के अलावा अन्य सभी निर्माण गतिविधियां चयनित स्थलों तक ही सीमित रहेंगी और आम जनता और आसपास के समुदाय के साथ हस्तक्षेप न्यूनतम है। इन कार्यों में, अस्थायी नकारात्मक प्रभाव मुख्य रूप से निर्माण धूल और शोर, निर्माण सामग्री के ढोने, स्थानीय सड़कों पर अपशिष्ट और उपकरण (यातायात, धूल, सुरक्षा आदि), निर्माण सामग्री के खनन, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पहलू (ओएच और एस) से उत्पन्न होते हैं।) । लोगों, गतिविधियों और यातायात से भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक

सड़कों के किनारे सीवर बिछाने का काम किया जाएगा। इसलिए इन कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अस्थायी प्रभाव मुख्य रूप से निर्माण कार्य के कारण निवासियों, व्यवसायों और यातायात की गड़बड़ी से उत्पन्न होते हैं; सड़क में गहरी खाई खोदने के कारण श्रमिकों, सार्वजनिक और आसपास के भवनों के लिए सुरक्षा जोखिम; घरों और व्यवसाय तक पहुंच में बाधा, बड़ी मात्रा में निर्माण कचरे का निपटान आदि। ये सभी शहरी क्षेत्रों में निर्माण के सामान्य प्रभाव हैं और शमन के अच्छी तरह से विकसित तरीके हैं जो ईएमपी में सुझाए गए हैं। 3.5 मीटर से अधिक गहरे सीवरों के लिए और यातायात क्षेत्रों में मुख्य सड़क/रेलवे क्रॉसिंग पर भी ट्रेचलेस पद्धति अपनाई जाएगी।

12. एक बार नई प्रणाली के संचालन के बाद, सुविधाएं नियमित रखरखाव के साथ संचालित होंगी, जिससे पर्यावरण को प्रभावित नहीं होना चाहिए। बेहतर सिस्टम ऑपरेशन सभी गतिविधियों के लिए विकसित किए जाने वाले संचालन और रखरखाव मैनुअल और मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

13. पर्यावरण प्रबंधन- उपयुक्त एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपने के साथ-साथ स्वीकार्य स्तर तक सभी नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए शमन उपाय प्रदान करने के लिए एक पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) विकसित की गई है। विभिन्न डिजाइन संबंधी उपाय पहले से ही परियोजना डिजाइन में शामिल हैं। निर्माण के दौरान, ईएमपी में शमन उपाय शामिल हैं जैसे (i) जनता की असुविधा को कम करने के लिए सीवर कार्यों की उचित योजना बनाना; (ii) बैरिकेडिंग, धूल दमन और नियंत्रण के उपाय; (iii) सड़कों के किनारे और ढोने की गतिविधियों के लिए यातायात प्रबंधन के उपाय; (iv) पहुंच सुनिश्चित करने के लिए खाइयों के ऊपर पैदल मार्ग और तख्तों का प्रावधान बाधित नहीं होगा; और (v) निपटान मात्रा को कम करने के लिए उत्खनित सामग्रियों का यथासंभव लाभकारी उपयोग करना। ईएमपी उप-परियोजना के पर्यावरण के अनुकूल निर्माण का मार्गदर्शन करेगा। ईएमपी में ईएमपी कार्यान्वयन की प्रभावशीलता को मापने के लिए एक निगरानी कार्यक्रम शामिल है और इसमें ऑन- और ऑफ-साइट अवलोकन, दस्तावेज जांच, और श्रमिकों और लाभार्थियों के साथ साक्षात्कार शामिल हैं। अद्यतन ईएमपी/एसईएमपी की एक प्रति निर्माण अवधि के दौरान हर समय साइट पर रखी जाएगी। ईएमपी को साइट पर काम करने वाले सभी ठेकेदारों के लिए बाध्यकारी बनाया जाएगा और इसे संविदात्मक खंडों में शामिल किया जाएगा। इस दस्तावेज में निर्धारित शर्तों के साथ गैर-अनुपालन, या कोई विचलन, अनुपालन में विफलता का गठन करेगा। संचालन चरण के प्रदर्शन की निगरानी के लिए, एसटीपी (कच्चे और उपचारित सीवेज गुणवत्ता), एसटीपी पर कीचड़ की उपचार दक्षता की निगरानी के लिए दीर्घकालिक सर्वेक्षण भी होंगे। इस तरह की कार्यवाहियों के लिए जिम्मेदार परियोजना एजेंसी के साथ शमन और निगरानी के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन योजना का हिस्सा हैं। ईएमपी की अनुमानित कार्यान्वयन लागत 31,137,700 रुपये है

14. इस दस्तावेज में निर्धारित शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रारूप IEE और EMP को बोली और अनुबंध दस्तावेजों में शामिल किया गया था। ठेकेदार ने समीक्षा और अनुमोदन के लिए पीआईईयू को एक अद्यतन ईएमपी / एसईएमपी प्रस्तुत किया है जिसमें (i) निर्माण कार्य शिविरों, भंडारण क्षेत्रों, सड़कों, बिछाने वाले क्षेत्रों, ठोस और खतरनाक कचरे के निपटान क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित स्थल / स्थान शामिल हैं; (ii) अनुमोदित ईएमपी के बाद विशिष्ट शमन उपाय; और (iii) ईएमपी के अनुसार निगरानी कार्यक्रम। एसईएमपी की मंजूरी से पहले किसी भी कार्य को शुरू करने की अनुमति नहीं है। ईएमपी/अनुमोदित एसईएमपी की एक प्रति निर्माण अवधि के दौरान हर समय साइट पर रखी गई है।

15. कार्यान्वयन व्यवस्था- राजस्थान सरकार का स्थानीय स्वशासन विभाग (LSGD) RUDSICO के माध्यम से कार्य कर रहा है, जो परियोजना निष्पादन एजेंसी है। पीएमयू को बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए रुडसिको के डिवीजन में रखा गया है। जयपुर और जोधपुर में दो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और प्रत्येक परियोजना शहर/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) में पीआईईयू हैं। पीएमयू एडीबी को पर्यावरण मूल्यांकन और निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने, सुरक्षा उपायों के अनुपालन की निगरानी, सुरक्षा उपायों के मुद्दों को संबोधित करने, पीआईईयू को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। पीआईईयू ईएमपी कार्यान्वयन,

सूचना प्रकटीकरण, परामर्श और अन्य क्षेत्र-स्तरीय गतिविधियों की दिन-प्रतिदिन की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। पीएमयू ने पर्यावरण के लिए एक परियोजना अधिकारी नियुक्त किया है और प्रत्येक पीआईयू ने एक सुरक्षा और सुरक्षा अधिकारी (एसएसओ) की प्रतिनियुक्ति की है। पीएमयू पर्यावरण परियोजना अधिकारी को परियोजना प्रबंधन और क्षमता निर्माण सलाहकार (पीएमसीबीसी) और निर्माण प्रबंधन और पर्यवेक्षण सलाहकार (सीएमएससी) के विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

16. परामर्श, प्रकटीकरण और शिकायत निवारण। हितधारकों को साइट पर चर्चा और शहर स्तर पर एक सार्वजनिक परामर्श कार्यशाला के माध्यम से आईईई विकसित करने में शामिल किया गया था, जिसके बाद व्यक्त किए गए विचारों को आईईई और परियोजना की योजना और विकास में शामिल किया गया था। साइट पर सार्वजनिक परामर्श के अलावा, शहर स्तरीय समिति (सीएलसी) की एक हितधारक बैठक आयोजित की गई और सीएलसी ने उप-परियोजना की सराहना की और उसे मंजूरी दी। IEE को सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराया जाएगा, IEE के मसौदे (Draft) और पहले अद्यतन (first updated) किए गए IEE का खुलासा किया गया था, और इस अद्यतन IEE (updated IEE) को ADB और RUDSICO वेबसाइटों के माध्यम से व्यापक दर्शकों के लिए भी प्रकट किया जाएगा। परियोजना कार्यान्वयन के दौरान परामर्श प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा और विस्तारित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हितधारक परियोजना में पूरी तरह से लगे हुए हैं और इसके विकास और कार्यान्वयन में भाग लेने के लिए तत्पर हैं। आईईई के भीतर एक शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) का वर्णन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी सार्वजनिक शिकायत का त्वरित समाधान किया जा सके।

17. निगरानी और रिपोर्टिंग- निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए पीएमयू, पीआईयू और सलाहकार जिम्मेदार होंगे। निर्माण के दौरान, डीबीओ ठेकेदार द्वारा आंतरिक निगरानी के परिणाम पीआईयू को उनकी मासिक ईएमपी कार्यान्वयन रिपोर्ट में दिखाई देंगे। सीएमएससी की सहायता से पीआईयू, ठेकेदार के अनुपालन की निगरानी करेगा, एक त्रैमासिक पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट (क्यूईएमआर) तैयार करेगा और पीएमयू को प्रस्तुत करेगा। पीएमयू कार्यान्वयन और अनुपालन की देखरेख करेगा और एडीबी को अर्ध-वार्षिक पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट (एसईएमआर) प्रस्तुत करेगा। एडीबी पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर डालेगा। निगरानी रिपोर्ट को रुडसिको-ईएमपी/पीएमयू वेबसाइट पर भी पोस्ट किया जाएगा।

18. निष्कर्ष और सिफारिशें- राजस्थान के नागरिक इसके प्रमुख लाभार्थी होंगे। उप-परियोजना मुख्य रूप से सीवरेज के प्रावधान के माध्यम से राजस्थान टाउन की पर्यावरणीय गुणवत्ता और रहने की स्थिति में सुधार के लिए डिजाइन की गई है। इस उप-परियोजना से होने वाले लाभों में शामिल हैं: (i) बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेष रूप से जलजनित और संक्रामक रोगों में कमी; (ii) भूजल प्रदूषण का कम जोखिम; (iii) उपचारित जल आपूर्ति के संदूषण के जोखिम को कम करना; और, उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के कारण ताजे जल संसाधन पर कम निर्भरता, और (iv) अनुपचारित अपशिष्ट के निपटान की रोकथाम के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार।

19. इसलिए उप-परियोजना से महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। डिजाइन, निर्माण और संचालन से जुड़े संभावित प्रभावों को उचित इंजीनियरिंग डिजाइन और अनुशंसित शमन उपायों और प्रक्रियाओं के समावेश या आवेदन के माध्यम से बिना कठिनाई के मानक स्तर तक कम किया जा सकता है। दूसरे अद्यतन आईईई के निष्कर्षों के आधार पर, कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है और परियोजना "बी" श्रेणी के रूप में जारी है। उप-परियोजना भारत सरकार की ईआईए अधिसूचना (2006) द्वारा कवर नहीं की गई है।

20. आईईई के दूसरे अपडेट के बाद; लगभग सभी परियोजना घटकों (सीवर नेटवर्क, एसपीएस, एसटीपी, सीआरएमसी आदि) के डिजाइन को मंजूरी दी गई है और केवल कुछ घटक जैसे एसटीपी से डिस्चार्ज प्वाइंट

तक उपचारित बहिःस्राव का बहिर्वाह, एफएसएसएम कार्य स्वीकृत नहीं हैं। शेष घटकों को अनुमोदित और अंतिम रूप दिए जाने पर इस आईईई को फिर से अद्यतन किया जाएगा।

26. सिफारिशें- कोई महत्वपूर्ण प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए उप-परियोजना पर लागू सिफारिशों का अनुपालन निम्नलिखित है:

अनुशंसाएँ जिनका इस IEE अद्यतन के दौरान पहले ही अनुपालन किया जा चुका है-

(i) जल्द से जल्द सभी वैधानिक मंजूरी प्राप्त करें और सुनिश्चित करें कि शर्तों/प्रावधानों को विस्तृत डिजाइन में शामिल किया गया है- अनुपालन किया गया

(ii) इस आईईई को बोली और अनुबंध दस्तावेजों में शामिल करें- ड्राफ्ट आईईई बोली और अनुबंध दस्तावेजों में शामिल है

(iii) विस्तृत डिजाइन के आधार पर इस आईईई को अपडेट/संशोधित करें और/या यदि अप्रत्याशित प्रभाव हों, तो दायरे, संरेखण, या स्थान में परिवर्तन- आईईई अपडेट किया जाता है

(iv) अनुबंध प्रदान करने पर ठेकेदार को सुरक्षा उपायों का संचालन करना- ठेकेदार को सुरक्षा प्रदान करना किया जाता है

(v) ईएमपी कार्यान्वयन का कड़ाई से पर्यवेक्षण करें- अनुपालन किया जा रहा है

(vi) सुनिश्चित करें कि ठेकेदार ने कार्य शुरू करने से पहले योग्य ईएचएस अधिकारियों को नियुक्त किया- अनुपालन किया- ठेकेदार द्वारा ईएचएस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है

(vii) दस्तावेजीकरण और नियमित आधार पर रिपोर्टिंग जैसा कि आईईई में दर्शाया गया है- किया जा रहा है

(viii) हितधारकों के साथ निरंतर परामर्श- किया जा रहा है

(ix) सूचना का समय पर प्रकटीकरण और शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) की स्थापना - जीआरएम स्थापित हो चुका है

(x) प्रथम स्तर के जीआरएम में उप-ठेकेदारों सहित ठेकेदारों की भागीदारी- अनुपालन किया गया

(xi) परियोजना कार्यान्वयन के दौरान पर्यावरण और लोगों को किसी भी प्रभाव से बचाने के लिए पीएमयू, पीआईयू, परियोजना सलाहकार और ठेकेदारों की प्रतिबद्धता- पीएमयू, पीआईयू, परियोजना सलाहकार और ठेकेदार सुरक्षा अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध हैं।

(xii) सुनिश्चित करें कि परियोजना स्थलों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2000 और उसके संशोधन के अनुसार नामित निपटान स्थलों में निपटाए गए ठोस अपशिष्ट और अन्य उपद्रव सामग्री से हटा दिया गया है;- अनुपालन किया जा रहा है

(xiii) सुनिश्चित करें कि फिकल स्लज (Faecal Sludge) प्रबंधन प्रोटोकॉल पर्यावरण नियमों (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2000 और इसके संशोधन) के अनुरूप हैं और ठोस अपशिष्ट निपटान में एक निर्दिष्ट साइट होनी चाहिए (खाली लॉट पर डंपिंग की अनुमति नहीं है); - अनुपालन किया जा रहा है।

सिफारिशें जो इस उप परियोजना पर लागू नहीं होती हैं-

(i) साइट-विशिष्ट स्थितियों के अनुसार एस्बेस्टस प्रबंधन योजना को अपडेट करें; - यह सीवरेज उप परियोजना है, परियोजना स्थलों पर कोई एसीएम मौजूद नहीं है या होने की उम्मीद नहीं है इसलिए एसीएम योजना की कोई आवश्यकता नहीं है।